

बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

25 फरवरी 2020

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 10

बेडों की संख्या में बढ़ोत्तरी

*1 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, पी.एम.सी.एच. के मेडिकल इमरजेंसी में प्रतिदिन 400 से 450 मरीज, जिन्हें जाड़े में ब्रेन हैमरेज, सांस की बीमारी, हर्ट अटैक, अनियंत्रित शुगर हो गया है, इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में बेड की कमी रहने के कारण उन मरीजों को जमीन पर या स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज किया जाता है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में सालोभर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, जबकि मेडिकल इमरजेंसी में मात्र 200 बेड सीमित हैं;

कर्ज दिये जाने की गति धीमी

*2 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

Will the **अल्पसंख्यक कल्याण** be pleased to state:-

क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में स्वरोजगार के द्वारा अल्पसंख्यकों को आर्थिक तरक्की देने हेतु अल्पसंख्यक वित्त निगम से अल्पसंख्यकों को कर्ज देने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि कर्ज देने हेतु सरकार से वित्त निगम को वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 100 करोड़ रुपये मिले, लेकिन 13 करोड़ 47 लाख रुपये कर्ज देने के रूप में बांटे गये;

(ग) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कर्ज दिये जाने की धीमी गति का क्या औचित्य है ?

पैथोलॉजिकल एवं एक्स-रे जांच की सुविधा कबतक

*3 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के शिवहर प्रखंड के फतहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के लिए पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा नहीं रहने के कारण मरीजों को बाहर जाकर जांच करवानी होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फतहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैथोलॉजिकल एवं एक्स-रे जांच की व्यवस्था करने हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कबतक

*4 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

Will the **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** be pleased to state:-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गयी, इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में गया जिले के 1970 वार्ड में करीब 2 लाख 83 हजार 680 घरों तक पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचाना है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अबतक मात्र 77 हजार 860 घरों में ही पानी

पहुंचाया गया है, जबकि 2 लाख 5820 घरों में पानी पहुंचना बाकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सही विद्युत तार की व्यवस्था

*5 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

Will the **ऊर्जा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर क्षेत्र में विद्युत पोलों पर लगातार लोड बढ़ने से आये दिन शार्ट सर्किट से बॉक्स में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बंजारी के पास विद्युत पोल में आग लग गई, आग इतनी तेज लगी कि बॉक्स के बाहर तक लपटें निकलने लगीं;

(ग) क्या यह सही है कि विद्युत पोल क्षतिगस्त होने से तार स्थानीय गलियों में झूलते रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो लोड के अनुसार तारों को परिवर्तित करने एवं झूलते तारों को सही करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बिजली दर में कमी

*6 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

Will the **उद्योग** be pleased to state:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना में बिहार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का प्रति किलो वाट फिक्स चार्ज 35 प्रतिशत और बिजली दर 30 प्रतिशत अधिक है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के उद्योग को मरने से बचाने के लिए 30 प्रतिशत बिजली दर कम करना जरूरी है, यदि सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार उद्योग के क्षेत्र में और पिछड़ जाएगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में उद्योग को विकसित करने के लिए 30 प्रतिशत बिजली दर कम करना चाहती है ?

सख्त कार्रवाई

***7 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

Will the **ऊर्जा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि बिहार में मार्च, 2016 से ईईएसएल कंपनी को एलईडी बल्ब बेचने के लिए अधिकृत किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि कंपनी द्वारा एलईडी बल्ब पर तीन वर्षों की गारंटी देने का वादा किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि एलईडी बल्ब बेचने वाले सभी काउंटर दिसंबर, 2017 से बंद कर दिए गए फलस्वरूप उपभोक्ता फ्यूज बल्ब को बदलने हेतु बिजली कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ईईएसएल कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है ?

प्रस्ताव समर्पित

***8 श्री मनोज यादव (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

: क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 6 शैय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से 30 शैय्या वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित प्रयोजनार्थ बी.एम.एस.आई.सी.एल. के अभियंताओं का समूह गठित कर राज्य के विभिन्न जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सर्वेक्षण कराया गया;

(ग) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु बाँका

जिले के फुल्लीडुमर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास जमीन उपलब्ध नहीं थी;

(घ) क्या यह सही है कि प्रखंड प्रमुख, फुल्लीडुमर, जिला-बांका द्वारा पत्रांक-09, दिनांक-07.03.2017 को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका को भूमि की उपलब्धता को स्वीकार करते हुए 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने का अनुरोध किया गया था;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'घ' में वर्णित प्रखंड प्रमुख फुल्लीडुमर, जिला-बांका द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन बी.एम.एस.आई.सी.एल. को उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*9 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

Will the गन्ना उद्योग be pleased to state:-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले की सुगौली चीनी मिल से जुड़े 25 हजार किसानों के गन्ना का बकाया 70 करोड़ की राशि कई सालों से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि सुगौली चीनी मिल द्वारा बकाये राशि के भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों के सामने भुखमरी चिकित्सा, शादी-विवाह एवं अन्य परेशानियों के कारण काफी असंतोष है तथा कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के लगभग 70 करोड़ की राशि का भुगतान अविलम्ब कराने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियमित भत्ता

*10 श्री टुनजी पाण्डेय (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):

Will the स्वास्थ्य be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य भर में आशा कार्यकर्ता सभी पंचायतों में कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इनको कोई नियमित भत्ता नहीं मिलता है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का एक हजार रुपया प्रतिमाह देने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आशा कर्मियों को 1000 रु. प्रतिमाह भत्ता देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?
